

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून:दिनांक 28 फरवरी, 2009

विषय:-सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ए0सी0पी0)
लागू किया जाना।

महोदय,

वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षण किया गया है तथा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

2-राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की भांति सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्ययन योजना (ए0सी0पी0) को निम्नलिखित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) उक्त योजना में राज्य सरकार के समूह क, ख, ग एवं घ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर वित्तीय स्तरोन्ययन का लाभ अनुमन्य होगा। उक्त लाभ उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुमन्य होगा जिनका कोई संगठित संवर्ग नहीं है अपितु वे एकल पद पर कार्यरत हैं तथा पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की योजना के अन्तर्गत उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह योजना उन संवर्गों के लिये नहीं होगी जिनकी संगत सेवानियमावली में पूर्व से ही समयमान/चयन वेतनमान/समयबद्ध प्रोन्नति

की व्यवस्था विद्यमान है जिसके कारण वित्तीय उत्थान/प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं।

(ग) उक्त योजना का लाभ कैजुअल, तदर्थ एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगा।

(घ) इस योजना का प्रभाव संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति/रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति के सोपानों पर नहीं पड़ेगा।

3-वित्तीय स्तरोन्नयन की शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

(क) योजना के अन्तर्गत कमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों में नियमित रूप से कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने की व्यवस्था होगी अर्थात् अधिकारियों/कर्मचारियों के मौलिक नियुक्ति के पद के ग्रेड वेतन से आलोच्य अवधि पूर्ण होने पर उसी शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 की तालिका के कॉलम-5 में अग्रेतर ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु फंक्शनल/नियमित पदोन्नति की भांति किसी पद के सापेक्ष स्तरोन्नयन नहीं होगा अपितु वर्तमान ग्रेड वेतन के ठीक बाद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ का अधिकतम स्तर वेतन बैंड-4 में वेतन बैंड रु० 37400-67000 पर रु० 8700 का ग्रेड वेतन (रु० 14300-18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान के स्तर तक) होगा इसके बाद के ग्रेड पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) सरकारी सेवक की 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, 20 वर्ष पर द्वितीय तथा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उपरोक्त प्रस्तर-3 (क) के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होगा। यदि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण प्रथम स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अग्रेतर बढ़ जाता है तब इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय एवं तृतीय स्तरोन्नयन पर भी उसी आधार पर पड़ेगा।

(घ) पूरे सेवा काल में सरकारी सेवक को सीधी भर्ती से उसकी प्रथम नियुक्ति के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होंगे। यदि प्रथम स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व कार्मिक की नियमित पदोन्नति हो जाती है और पदोन्नति होने में यदि पदवारक उग्राडलिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 की तालिका-5 में अपने मूल

पद के अगले ग्रेड वेतन में यदि पदोन्नति होता है तो उसे द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन में अगले ग्रेड वेतन क्रमशः 20 एवं 30 वर्षों में प्राप्त होंगे। यदि प्रथम पदोन्नति में ही पदधारक के मूल पद के ग्रेड वेतन से पदोन्नति होने पर दो स्तर उच्च का ग्रेड वेतन अनुमन्य होता है ऐसी स्थिति में क्योंकि उसे प्रथम पदोन्नति में ही द्वितीय स्तरोंन्नयन का लाभ 10 वर्ष के अन्दर प्राप्त हो गया है ऐसी स्थिति में पूरे सेवा काल में अनुमन्य तीन वित्तीय स्तरोंन्नयन के अन्तर्गत आगामी वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर ही अनुमन्य होगा। यदि कार्मिक को अपने मूल संवर्ग के पद से क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही दो पदोन्नति होने पर तीन वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना का भविष्य में कोई अन्य लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(ड) उपरोक्त प्रस्तर-3(ब) उन कार्मिकों पर भी लागू होगा जिनको वेतन समिति (1997-1999) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-1996 से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या-1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों के अधीन क्रमशः 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के पद के वेतनमान के अनुसार अनुमन्य किये गये वेतनमानों से यदि उपरिलिखित शासनादेश 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 की तालिका-5 के अनुसार उसके मूल पद के सादृश्य यदि क्रमशः 1, 2 या 3 उच्च स्तर के वित्तीय स्तरोंन्नयन प्राप्त हो चुका है तो उसे क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो पर अनुमन्य हो जाने पर उक्त योजनाका लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उक्त वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ कार्मिक को पूर्णतः वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जायेगा और इसका उसकी वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. उक्त योजना के अन्तर्गत कार्मिक के वेतन का निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 (एक) के अनुसार किया जायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ अन्तिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय उसे वेतन निर्धारण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6. उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य उच्च वित्तीय स्तरों पर इस शर्त के अधीन होगा कि भविष्य में होने वाली रिक्ति पर उसकी पदोन्नति होती है तो वह उसे लेने के लिये बाध्य होगा।

7. यदि कोई कार्मिक उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरों पर लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित पदोन्नति को अस्वीकार करता है तो उक्त योजना के अन्तर्गत उसे अनुमन्य लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उक्त योजना के अन्तर्गत उसे आगामी वित्तीय स्तरों पर लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

8. उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 के कॉलम-4 में क्रमांक -1 से 14 तक वेतन बैंड क्रमशः रू0 4440-7440 पर रू0 1300 का ग्रेड वेतन (रू0 2550-3200 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) से रू0 9300-34800 के वेतन बैंड पर रू0 4800 के ग्रेड वेतन (रू0 7500-12000 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) तक के पदधारकों के लिये उक्त योजना दिनांक 1-9-2008 से तथा वेतन बैंड 15600-39100 पर रू0 5400 के ग्रेड वेतन (रू0 8000-13500 का दिनांक 1-1-2006 से पूर्व का वेतनमान) तक के कार्मिकों को उक्त योजना का लाभ दिनांक 1-1-2006 से अनुमन्य होगा। यदि वेतन बैंड-3 के उक्त प्रारम्भिक पद पर किसी विभाग के किसी पद के एकल या एक से अधिक पद होने पर भी समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अधीन उसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2006 से पूर्व भी पूर्ण करने पर भी उक्त योजना का लाभ दिनांक 1-1-2006 से अथवा उक्त तिथि के बाद जहां भी वे 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हों, अनुमन्य होगा। ऐसे कार्मिकों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ क्रमशः 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर प्राप्त होंगे।

9. सुनिश्चित वित्तीय स्तरों पर/एशोर्ड कैरियर स्तरों पर योजना (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि से समयमान वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या-1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च 2001 एवं उक्त के क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश निरस्त समझे जायेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 75 (1)/xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा रो
 7/2
 (टी0एन0सिंह)
 अपर सचिव।